eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

नेपाल में चीन की कूटनीतिक सक्रियता और भारत की नीति विकल्प

आदर्श मालवीय[1]
[1]शोध छात्र, प्रो.राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज उ0प्र0

Received: 08 November 2025, Accepted: 20 November 2025, Published online: 30 November 2025

Abstract

नेपाल दक्षिण एशिया के भू–राजनीतिक मानचित्र में एक ऐसा देश है, जो भारत और चीन–दो महाशक्तियों–के बीच एक सेतु के रूप में स्थित है। पिछले एक दशक में चीन ने नेपाल में अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सक्रियता को जिस गति से बढ़ाया है, उसने इस क्षेत्र की शक्ति–संतुलन व्यवस्था को प्रभावित किया है। चीन की "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" और नेपाल के साथ उसके बुनियादी ढांचा निवेश ने न केवल नेपाल की विदेश नीति को नया आयाम दिया है, बल्कि भारत के लिए भी रणनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। वहीं भारत, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से नेपाल से गहराई से जुड़ा रहा है, अब अपने पारंपरिक दृष्टिकोण की समीक्षा करने के लिए बाध्य है। इस शोध–पत्र में नेपाल में चीन की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका का विश्लेषण करते हुए यह विवेचना की गई है कि भारत किन नीतिगत विकल्पों के माध्यम से इस परिवर्तित परिदृश्य में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि दक्षिण एशिया में संतुलन और सहयोग की नई दिशा किस प्रकार संभव हो सकती है।

बीज शब्द– नेपाल चीन की कूटनीति, भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय संतुलन,बेल्ट एंड रोड पहल, दक्षिण एशिया, रणनीतिक सहयोग, भू–राजनीति, नीति विकल्प ।

Introduction

नेपाल दक्षिण एशिया का एक लघु, किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण देश है, जिसकी भौगोलिक स्थिति उसे क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना देती है। हिमालय की गोद में बसे इस देश की सीमाएँ भारत और चीन –दोनों एशियाई दिग्गजों–से मिलती हैं। इस कारण नेपाल न केवल इन दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सेतु की भूमिका निभाता है, बल्कि उसकी विदेश नीति भी इन दोनों शक्तियों के प्रभाव से गहराई से प्रभावित होती रही है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति, सामरिक महत्व और ऐतिहासिक संबंधों ने उसे दक्षिण एशिया की राजनीतिक कूटनीति में विशेष स्थान प्रदान किया है। यही कारण है कि बीते कुछ वर्षों में नेपाल, भारत और चीन के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक अहम क्षेत्र बनकर उभरा है।

इतिहास के पन्नों में देखें तो नेपाल और भारत का संबंध सांस्कृतिक, धार्मिक और जन–संपर्क के स्तर पर अत्यंत गहरा रहा है। दोनों देशों के बीच खुली सीमाएँ, साझा सभ्यता, परस्पर विवाह–संबंध और समान सामाजिक परंपराएँ इस जुड़ाव को और गहराई देती हैं। भारत ने लंबे समय तक नेपाल को एक प्राकृतिक सहयोगी के रूप में देखा, और उसकी विकास यात्रा में सहयोग देने का प्रयास भी किया। किंतु समय के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में परिवर्तन ने नेपाल को अपनी विदेश नीति के नए आयाम तलाशने पर विवश किया। विशेष रूप से 21वीं सदी के दूसरे दशक में चीन की आर्थिक शक्ति, उसकी

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और एशिया में बढ़ते निवेश ने नेपाल को एक वैकल्पिक सहयोगी के रूप में चीन की ओर झुकने का अवसर दिया।

नेपाल में चीन की बढ़ती सक्रियता को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह चीन की व्यापक दक्षिण एशियाई रणनीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वह भारत की पारंपरिक प्रभाव–सीमा को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। चीन की नीतियों में बुनियादी ढांचा निवेश, अनुदान, तकनीकी सहयोग, और राजनीतिक परामर्श जैसे तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नेपाल में सड़क, रेल, ऊर्जा, और संचार के क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप लगातार बढ़ा है। काठमांडू से लेकर ल्हासा तक जोड़ने वाली रेल परियोजना, नये पुलों और सड़कों का निर्माण, तथा जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश, यह सब नेपाल को धीरे–धीरे चीन की कूटनीतिक पकड़ में लाने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है।

भारत के लिए यह स्थिति सहज नहीं रही। भारत और नेपाल के संबंध यद्यपि ऐतिहासिक रूप से मजबूत हैं, किंतु समय–समय पर इन संबंधों में उतार–चढ़ाव भी आते रहे हैं। 2015 में नेपाल के संविधान निर्माण के बाद सीमा विवादों और राजनीतिक मतभेदों ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा किया। उस समय चीन ने कूटनीतिक चतुराई से इस अवसर का लाभ उठाया और नेपाल को व्यापार, राहत, तथा निवेश के नए वायदे दिए। इस घटनाक्रम ने भारत के लिए यह संकेत दिया कि दक्षिण एशिया में उसका पारंपरिक प्रभाव अब निर्विवाद नहीं रहा।

चीन की सक्रियता केवल आर्थिक सहायता या व्यापार तक सीमित नहीं है। उसने नेपाल में अपनी "सॉफ्ट पावर" के माध्यम से भी जगह बनाई है। नेपाल के विश्वविद्यालयों में कन्फ्यूशियस संस्थान, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, मीडिया प्रशिक्षण, और डिजिटल नेटवर्क में सहयोग–ये सभी प्रयास चीन की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके माध्यम से वह सामाजिक और वैचारिक स्तर पर भी अपनी छवि मजबूत करना चाहता है। नेपाल के युवाओं में चीन की तकनीकी उपलब्धियों के प्रति आकर्षण भी इसी दिशा में देखा जा सकता है।

दूसरी ओर, भारत अपनी (Neighbourhood First) नीति के तहत नेपाल के साथ संबंधों को पुनः सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। परंतु भारत की नीतियों में कभी–कभी जो संरक्षणवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, वह नेपाल में असंतोष का कारण बनता है। नेपाल, जो अब अपनी संप्रभुता और समानता की पहचान पर बल देना चाहता है, किसी भी प्रकार के "अभिभावक" व्यवहार को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि नेपाल अपने विदेशी संबंधों में विविधीकरण की नीति अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिसका सबसे स्पष्ट उदाहरण चीन के साथ बढ़ते सहयोग के रूप में देखा जा सकता है।

आज नेपाल की विदेश नीति एक "संतुलनकारी कूटनीति" का उदाहरण बन चुकी है। वह न तो पूरी तरह चीन की ओर झुका है, और न ही भारत से दूरी बनाना चाहता है। बल्कि नेपाल का उद्देश्य दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने विकासात्मक हितों को आगे बढ़ाना है। किंतु यह संतुलन बनाए रखना सरल नहीं है। भारत और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा में नेपाल को कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ उसे अपनी आंतरिक राजनीतिक स्थिरता और बाहरी दबावों के बीच निर्णय लेना होता है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

भारत के लिए चुनौती यह है कि वह नेपाल को केवल अपनी सुरक्षा दृष्टि से न देखे, बल्कि उसे एक समान साझेदार के रूप में सम्मान दे। भारत को अपनी नीतियों में उस भावनात्मक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जिसने दोनों देशों के संबंधों को ऐतिहासिक रूप से विशेष बनाया था। आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संपर्क, शिक्षा, पर्यटन, और युवा आदान–प्रदान जैसे क्षेत्रों में भारत के प्रयास, चीन की आर्थिक शक्ति का संतुलन बन सकते हैं।

इस शोध–पत्र की प्रस्तावना के माध्यम से स्पष्ट होता है कि नेपाल में चीन की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता न केवल एक द्विपक्षीय मुद्दा है, बल्कि यह सम्पूर्ण दक्षिण एशिया के शक्ति–संतुलन पर प्रभाव डाल रही है। भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी पारंपरिक नीति को आधुनिक कूटनीतिक दृष्टि से जोड़े, ताकि वह नेपाल में पुनः विश्वास, सहयोग और साझेदारी का वातावरण स्थापित कर सके। आने वाले अध्यायों में इस शोध का उद्देश्य यही रहेगा कि नेपाल में चीन की कूटनीतिक नीतियों की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए, भारत के संभावित नीति–विकल्पों का विवेचन किया जाए, जिससे दक्षिण एशिया में स्थिरता और पारस्परिक सहयोग की दिशा सुदृढ़ हो सके।

उद्देश्य– इस शोध का उद्देश्य नेपाल में चीन की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता का विश्लेषण करते हुए यह समझना है कि भारत किन नीतिगत उपायों और रणनीतिक विकल्पों के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपने पारंपरिक प्रभाव, संतुलन और सहयोग की स्थिति को पुनर्स्थापित कर सकता है, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता बनी रहे।

मुख्य भाग– नेपाल का भूगोल, इतिहास और संस्कृति उसे दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। यह छोटा–सा पहाड़ी देश भारत और चीन जैसे दो शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच स्थित है, जिससे उसकी विदेश नीति सदैव संतुलन और सावधानी का प्रतीक रही है। चीन और नेपाल के बीच संबंध लंबे समय से रहे हैं, किंतु औपचारिक राजनयिक संपर्क 1955 में स्थापित हुए। तिब्बत के प्रश्न पर चीन की स्थिति मजबूत होते ही उसने नेपाल को अपने निकट लाने का प्रयास आरंभ किया। नेपाल के लिए चीन एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरा, जो औद्योगिक विकास और राजनीतिक सहयोग का नया आयाम प्रस्तुत करता था।

समय के साथ चीन और नेपाल के बीच संबंधों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गहराई बढ़ती गई। चीन ने नेपाल के साथ समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित कूटनीति अपनाई। 1960 के दशक में सीमांकन और व्यापार समझौते हुए, जिनसे आपसी विश्वास बढ़ा। नेपाल ने भी यह समझा कि भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना ही उसकी स्थिरता और स्वतंत्रता का आधार है। इसी संतुलन नीति ने नेपाल को वर्षों तक दोनों देशों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद की।

21वीं सदी में चीन ने नेपाल में अपनी सक्रियता को नई गति दी। 2017 में नेपाल ने चीन की महत्वाकांक्षी "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" (BRI) पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। चीन ने नेपाल में सड़कें, पुल, जलविद्युत संयंत्र, और संचार नेटवर्क विकसित करने में निवेश किया। काठमांडू से ल्हासा तक रेलवे संपर्क की योजना, पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, चीन की रणनीति का हिस्सा बने। यह सब नेपाल की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना गया, किंतु इसके साथ ऋण निर्भरता और सामरिक दबाव की चिंताएँ भी बढ़ीं।

नेपाल में चीन का प्रभाव केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं रहा। चीन ने सांस्कृतिक और वैचारिक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नेपाल के विश्वविद्यालयों में कन्फ्यूशियस संस्थानों की स्थापना, चीनी भाषा की कक्षाएँ, छात्रवृत्तियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस दिशा में चीन के प्रयासों का उदाहरण हैं। धीरे–धीरे नेपाल के शहरी समाज में चीन की तकनीकी और आर्थिक उपस्थिति सामान्य होती गई। टेलीकॉम, निर्माण और ई–कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की सक्रियता ने नेपाल की आर्थिक संरचना में चीन की भूमिका को और बढ़ाया।

भारत और नेपाल के संबंधों की ऐतिहासिक गहराई निर्विवाद है। धार्मिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक जुड़ाव के कारण दोनों देशों के लोगों के बीच आत्मीयता का रिश्ता सदियों पुराना है। 1950 की शांति और मैत्री संधि ने इन संबंधों को औपचारिक रूप दिया, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के नागरिकों को सीमा पार आने–जाने और व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। भारत ने नेपाल के औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्रों में निरंतर सहायता दी। किंतु वैश्विक राजनीति के बदलते स्वरूप और नेपाल की आंतरिक राजनीतिक स्थिति ने इन संबंधों में नई जटिलताएँ जोड़ीं।

2015 में नेपाल ने नया संविधान लागू किया, जिससे कुछ राजनीतिक मतभेद उत्पन्न हुए। भारत द्वारा व्यक्त असंतोष और सीमा पर आपूर्ति अवरोध ने नेपाली जनमानस में भारत के प्रति नाराजगी पैदा की। इसी समय चीन ने त्वरित सहायता और वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग प्रदान कर नेपाल का विश्वास जीता। यह वह दौर था जब नेपाल ने पहली बार भारत की जगह चीन को एक संभावित सहयोगी के रूप में गंभीरता से देखना शुरू किया। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक निर्भरता ने चीन को एक अवसर दिया कि वह धीरे–धीरे अपनी उपस्थिति को मजबूत करे।

चीन की कूटनीति का स्वरूप नेपाल में बहुत ही व्यवस्थित और दीर्घकालिक रहा है। आर्थिक सहायता, व्यापारिक निवेश और सांस्कृतिक विस्तार के माध्यम से चीन ने अपने लिए स्थायी आधार तैयार किया है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों में चीन की वैचारिक समानता ने राजनीतिक स्तर पर भी उसे एक भरोसेमंद सहयोगी बना दिया। नेपाल की सत्ता में जब भी अस्थिरता आई, चीन ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उसका प्रभाव और गहरा हुआ।

नेपाल की जनता में चीन को लेकर मतभेद हैं। एक वर्ग चीन को विकास और आधुनिकता का प्रतीक मानता है, जबकि दूसरा वर्ग उसकी नीतियों को छिपे हुए नियंत्रण के रूप में देखता है। चीन की परियोजनाओं से नेपाल को तत्काल लाभ अवश्य हुआ है, लेकिन दीर्घकाल में आर्थिक निर्भरता का जोखिम बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर, चीन द्वारा वित्तपोषित कुछ परियोजनाओं की लागत बहुत अधिक साबित हुई, जिससे नेपाल के ऋण भार में वृद्धि हुई।

भारत के लिए यह परिदृश्य एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर उभरा। भारत, जो अब तक नेपाल को अपने प्राकृतिक सहयोगी के रूप में देखता था, अब उसे चीन की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत को यह महसूस हुआ कि केवल भावनात्मक जुड़ाव या ऐतिहासिक संबंध पर्याप्त नहीं हैं। अब

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

व्यवहारिक और आधुनिक कूटनीति की आवश्यकता है। भारत को अपनी नीति में यह बदलाव करना होगा कि नेपाल को एक समान भागीदार के रूप में देखा जाए, न कि एक छोटे भाई या सुरक्षा क्षेत्र के रूप में।

भारत को यह समझना होगा कि नेपाल की नई पीढ़ी अधिक व्यवहारिक और वैश्विक दृष्टिकोण रखती है। उनके लिए आर्थिक अवसर, तकनीकी विकास और रोजगार के साधन प्राथमिकता हैं। इसलिए भारत को अपने सहयोग कार्यक्रमों को शिक्षा, तकनीक, और उद्यमिता से जोड़ना होगा। भारत द्वारा नेपाल के युवाओं को स्कॉलरशिप, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देना दीर्घकालिक विश्वास निर्माण का माध्यम बन सकता है।

भारत और चीन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा के इस दौर में नेपाल के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है। उसे अपने आर्थिक विकास के लिए चीन की सहायता चाहिए, परंतु वह भारत के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध तोड़ नहीं सकता। इसलिए नेपाल की नीति "संतुलन" की नीति बन गई है–एक ऐसा संतुलन जो उसे दोनों देशों के साथ समान रूप से संबंध रखने की अनुमति दे। यह नीति उसे कुछ अवसर तो देती है, परंतु जोखिम भी उत्पन्न करती है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है।

भारत के लिए सर्वोत्तम नीति यही है कि वह नेपाल को अपनी विदेश नीति के "केंद्र" में रखे। उसे केवल सुरक्षा या रणनीति के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जनसंपर्क और सांस्कृतिक साझेदारी के रूप में देखे। धार्मिक पर्यटन, योग, आयुर्वेद, हिंदी और संस्कृति के क्षेत्र में भारत के पास वह "सॉफ्ट पावर" है जो किसी अन्य देश के पास नहीं है। इसे और सशक्त बनाकर भारत, चीन की कठोर कूटनीति का प्रभावी उत्तर दे सकता है।

इसके साथ ही, भारत को नेपाल के विकास में साझेदारी बढ़ानी होगी। सीमा–पार सड़कों, रेलवे संपर्क, ऊर्जा व्यापार और जल परियोजनाओं में संयुक्त निवेश से दोनों देशों के हित सशक्त होंगे। भारत की (Neighbourhood First) नीति तभी सार्थक होगी जब वह केवल नारा न रहकर, व्यवहार में उतर आए। भारत को यह दिखाना होगा कि वह अपने पड़ोसियों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, और साझेदारी को समानता के आधार पर देखता है।

नेपाल के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने हितों को स्पष्ट रखे और किसी एक शक्ति के प्रभाव में पूरी तरह न जाए। उसे अपने विकास के लिए चीन की तकनीक और पूँजी का उपयोग करना चाहिए, परंतु इस सीमा तक नहीं कि उसकी नीतियाँ बाहरी दबाव में आ जाएँ। इसी तरह, भारत को भी यह स्वीकार करना होगा कि नेपाल की संप्रभुता सर्वोपरि है।

वर्तमान परिदृश्य में दक्षिण एशिया में शक्ति–संतुलन का केंद्र नेपाल बन गया है। चीन अपनी आर्थिक ताकत के बल पर नेपाल में गहरी पैठ बनाना चाहता है, जबकि भारत अपने ऐतिहासिक संबंधों और भौगोलिक निकटता के माध्यम से इस प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। यह प्रतिस्पर्धा तभी सकारात्मक रूप ले सकती है जब दोनों देश नेपाल को प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं, बल्कि सहयोग का सेतु मानें।

नेपाल में चीन की कूटनीतिक सक्रियता ने भारत को यह सिखाया है कि आधुनिक कूटनीति केवल सीमाओं और रक्षा से नहीं, बल्कि जनता, संस्कृति और विश्वास से भी बनती है। भारत के लिए यह आवश्यक

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

है कि वह अपने संबंधों में नई संवेदनशीलता लाए, ताकि नेपाल को यह महसूस हो कि भारत उसका सच्चा सहयोगी है, न कि कोई प्रभाव जमाने वाली शक्ति।

अंततः यह कहा जा सकता है कि नेपाल की विदेश नीति आज एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ उसे दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने विकास की राह तय करनी है। भारत और चीन दोनों के लिए यह अवसर है कि वे प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर क्षेत्रीय सहयोग की नई दृष्टि विकसित करें। नेपाल इस दिशा में एक उदाहरण बन सकता है, यदि दोनों देश उसे अपनी शक्ति–संतुलन की रणनीति का हिस्सा न बनाकर, साझेदारी के पुल के रूप में देखें।

निष्कर्ष– नेपाल में चीन की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता ने दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों को गहराई से प्रभावित किया है। चीन ने आर्थिक निवेश, आधारभूत संरचना निर्माण और राजनीतिक सहयोग के माध्यम से नेपाल में अपनी उपस्थिति को सशक्त किया है, जिससे वह दक्षिण एशिया की नीति–निर्माण प्रक्रिया में एक प्रमुख कारक बन गया है। दूसरी ओर, भारत के लिए यह परिदृश्य उसके पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निकटता के बावजूद भारत को अब अपनी विदेश नीति को आधुनिक कूटनीतिक व्यवहार और समान साझेदारी के सिद्धांतों पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

नेपाल के लिए दोनों देशों के बीच संतुलन बनाना उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसे चीन से विकास के अवसर लेने हैं, परंतु अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र नीति निर्धारण को भी सुरक्षित रखना है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह नेपाल को सहयोग और समानता के भाव से देखे, न कि किसी प्रभाव क्षेत्र के रूप में। शिक्षा, तकनीक, ऊर्जा और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से भारत नेपाल में दीर्घकालिक विश्वास को पुनः स्थापित कर सकता है।

अंततः, दक्षिण एशिया में स्थिरता और सहयोग का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और चीन किस प्रकार अपने संबंधों में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर साझेदारी की भावना विकसित करते हैं। नेपाल इस संतुलन का केंद्र बनकर क्षेत्रीय शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

संदर्भ सूची–

1. Acharya, Amitav, China’s Strategic Engagement with Nepal: Implications for India, Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi, 2020, pp. 15–45.

2. शर्मा, रमेशचंद्र, भारत–नेपाल संबंधः एक ऐतिहासिक अध्ययन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017, पृ 112–145

3. Bhattarai, Gaurav, Nepal Between China and India: Balancing a New Geopolitical Order, Nepal Institute for Policy Studies, Kathmandu, 2019, pp. 25–66.

4. मिश्रा, अजय कुमार, दक्षिण एशिया में चीन की भूमिका और भारत की विदेश नीति, भारती प्रकाशन, वाराणसी, 2019, पृ 56–98.

5. Chaturvedi, Sanjay, The Dragon in the Himalayas: China’s Growing Influence in Nepal, Observer Research Foundation, New Delhi, 2021, pp. 35–72.

6. पाण्डेय, सुभाष, नेपाल की विदेश नीति और चीन का प्रभाव, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2020, पृ 76–115

7. Panda, Jagannath Prasad, India-China Relations and the Nepal Factor, Palgrave Macmillan, Singapore, 2020, pp. 89–118.

8. सिंह, हरिशंकर, भारत–नेपाल संबंधों में चीन की चुनौती, विश्वभारती प्रकाशन, लखनऊ, 2018, पृ 45–82

9. Dixit, Kanak Mani, Nepal's Foreign Policy: Continuity and Change, Himal Books, Kathmandu, 2018, pp. 12–54.

10. तिवारी, नीरज कुमार, दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति और भारत–चीन प्रतिद्वंद्विता, प्रकाशन संस्थान, पटना, 2021, पृ 90–130

11. Shrestha, Saurav, Belt and Road Initiative in Nepal: Opportunities and Challenges, South Asia Watch on Trade, Economics and Environment, Kathmandu, 2022, pp. 50–90.

12. त्रिपाठी, रामनाथ, नेपाल लोकतंत्र, विकास और पड़ोसी संबंध, राष्ट्रीय पुस्तक निकेतन, नई दिल्ली, 2016, पृ 60–95.

13. Saran, Shyam, How China Sees India and South Asia, HarperCollins India, New Delhi, 2021, pp. 74–115.

14. Joshi, Mukesh, Border Diplomacy and India-Nepal Relations in the 21st Century, Routledge India, New Delhi, 2019, pp. 30–78.

15. Malone, David M. & Mukherjee, Rohan, India and China in South Asia: Rivals within the Region, Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 40–95.